International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 04, October - December, 2019, pp.43-46

सामाजिक लाभ – अनुलाभ विश्लेषण (जालोर ग्रेनाइट उदयोग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. जसराज बोहरा*
महिपाल सिंह दहिया**

सार

राजस्थान की औधोगिक इकाईयों का सामाजिक दायित्वों तथा व्यापारिक लाभों का सामाजिक विश्लेषण करना समय की प्रमुख मांग है। यदि राजस्थान के मारवाड क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सामाजिक दायित्वों और पर्यावरण संतुलन की महान परम्परा रही है। आज भी सामाजिक दायित्वों की निर्वाह के तौर पर पश्चिमी राजस्थान के पीने के पानी की व्यवस्थाएं सामाजिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान सदा करते आये है। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में भी सामाजिक दायित्वों के मद्देनजर ही अस्पताल, स्कूल और प्याउ आदि का निर्माण हमारी सामाजिक परम्परा रही है। इन सभी सामाजिक दायित्वों की पूर्ति एवं क्षेत्र के विकास में सरकार के साथ–साथ औधोगिकी इकाइयों का योगदान अपने नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में कितना है इसका मूल्याकंन करना भी इस विषय का मुख्य उद्धेश्य है। चूंकि यह विषय सामाजिक लागत अनुलाभ का है तो इसमें यह जानने का प्रयास है कि यह उधोग समाज को क्या–क्या दे रहा है तथा इसके विपरित इसके खनन से तथा अन्य साधनों को प्रयोग में लाने की लागत क्या आती है तथा यह प्रकृति पर ज्यादा नुकसान दे तो नही है।

शब्दावली: *लागत –अनुलाभ विश्लेषण, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), विनिमय दर।*

परिचय

जालोर राजस्थान के दक्षिणी –पश्चिम में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर प्राचीन काल में 'जाबालिपुर' नाम से जाना जाता था। जालोर नाम जाल–ओर शब्दो से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जाल नामक वृक्ष की सीमा से बना हुआ नगर।

tkykj dh vk/kkfxd fLFkfr

जालोर जोधपुर संभाग में स्थित एक ऐतिहासिक जिला है। जालोर का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 के जनसख्या आंकडो के अनुसार 1828730 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 936643 तथा महिलाओं की संख्या 892096 वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकडों के अनुसार है। जालोर जनसंख्या घनत्व 172 वर्ग प्रति किलोमीटर है। जालोर की साक्षरता प्रतिशत 55.58 प्रतिशत है। (अर्थात् 1210826 व्यक्ति साक्षर है) जालोर जिले को 9 तहसील, 264 ग्राम पंचायत, 724 गांवो में विभाजित किया जाता है। जालोर जिले में एक नगर परिषद जालोर व दो नगर पालिकाऐं भीनमाल तथा सांचौर है।

tkykj xzukbV m/kkx dk ifjp; RkFkk vkdkj

जालोर को ग्रेनाइट उत्पादन के लिये सिरमोर माना जाता है इसलिए जालोर की पहचान विश्वभर में ग्रेनाइट नगरी के रूप में है। जालोर का आर्थिक विकास ही पुरी तरह से ग्रेनाइट उधोग पर टिका हुआ है। जालोर से ग्रेनाइट दूसरे राज्यो के साथ–साथ अन्य देशो को भी निर्यात किया जाता है।

---

* विभागाध्यक्ष, लेखाकन विभाग, वाणिज्य एवं प्रबंन्ध अध्ययन संकाय, जे.एन.वी.यू., जोधपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, लेखाकन विभाग, वाणिज्य एवं प्रबंन्ध अध्ययन संकाय जे.एन.वी.यू. जोधपुर, राजस्थान।

जालोर को ग्रेनाइट उत्पादन/खनन व निर्यात के लिए अधिक प्रसिद्वि मिली इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर की टाईल्स बनाने का कार्य सबसे पहले जालोर में प्रारम्भ हुआ।

- भारत सरकार के भू–राजस्व सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद राजस्थान सरकार का ध्यान इस उधोग की ओर गया। इस रिपोर्ट में ग्रेनाइट पत्थरों के क्षेत्रो को दर्शाया गया।
- वर्ष 1965 में राजस्थान सरकार ने खान एवं भू–विज्ञान विभाग के माध्यम से एक ग्रेनाइट इकाई जालोर में स्थापित की जिसमें सारा काम हाथ से होता था।
- वर्ष 1971 में इसे राजस्थान उधोग एवं खनिज विकास कार्पोरेशन के अन्तर्गत लाया गया।
- वर्ष 1987 में निजी क्षेत्र भी ग्रेनाइट उत्पादन व विक्रय के क्षेत्र में प्रविष्टि हुआ और तब से निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग एकाधिकार सी हो चुकी है।

जालोर जिले में वर्तमान में 1500 ग्रेनाईट इकाईयां तथा 450 खाने है जिनमें 40000 लोगो को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है एवं इसमें 20000 की संख्या में श्रमिक के रूप में इस उधोग से जुडे हुए है, इसलिए जिले की अर्थव्यवस्था में 70 से 80 प्रतिशत की भागीदारी इस उधोग की है ग्रेनाइट उधोग का सालाना करोडों रूपयों का कारोबार किया जाता है।

Lkkekftd ykxr&vuqykHk fo'ys"k.k

एक व्यवसायिक ईकाई ही एक सामाजिक ईकाई है। वह समाज के संसाधनों का इस्तेमाल कर के ही वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करती है जिसका कि समाज ही एक मात्र उपभोक्ता होता है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय को समाज पनपने नही देता जो समाज के लिए अनुरूप नही होता है। उसी प्रकार समाज यह भी देखता है कि उस व्यवसाय की सामाजिक लागत उसके सामाजिक अनुलाभ से कम तो नही है। यहां सामाजिक अनुलाभ का तात्पर्य किसी समाज तथा उसके घटकों के आर्थिक तथा अनार्थिक अनुलाभों से है तथा सामाजिक लागत का तात्पर्य उस समाज तथा उसके घटकों के आर्थिक तथा अनार्थिक लागतों से है।

सामाजिक पद्धति की परियोजनाओं में मुख्यतः सामाजिक उद्धेश्यों व सरकारी परियोजनाओं को शामिल कर सकते है। मोटे तौर पर कहें तो बाजार ही समाज है। जैसे कि रेलवे परियोजना में यात्रियों और भाडे पर माल लाने व भेजने वालों को ही बाजार में सम्मिलित किया जायेगा। इसलिए बाजार का महत्व निजी संस्थाओं से जरा हट के होता है। इस के साथ ही सारे लागत–अनुलाभों को हम रूपयों में नही नाप सकते है। वे तो हम समाज के हित या अहित के रूप में देख सकते है। ऐसा विश्लेषण जो समाज में मोटें तौर पर कल्याण की दृष्टि रखता हो तो उसे हम सामाजिक लागत–अनुलाभ विश्लेषण कह सकते है।

समाजिक लागत अनुलाभ विश्लेषण करते समय जो लागत बाजार दर से ली जाती है उससे वास्तविक लागत दर्शाने में काफी फेर बदल की जरूरत होती है उस लागत में कई कर शुल्क आदि शामिल नही कर पाते। कई मजदूरी कानूनों के रहते हुए मजदूरों की अवसर लागत को बाजार दर में अच्छी तरह से दर्शा पाना असंभव है। अशिक्षित मजदूरों की वास्तविक लागत बाजार मजदूरों से कम होगी तथा शिक्षित मजदूरों की बाजार दर से अधिक ही होगी।

अगर एक परियोजना में एक मजदूर नियुक्त है और उसके लिए इसके अलावा कही भी अन्य जगह पर नियुक्ति की कोई भी संभावना नहर नही आ रही है तो सामाजिक माने में उस मजदूर की लागत शून्य के बराबर है। उन लागतों को ध्यान में रखना चाहिए जो साधनों की कमी के कारण अन्य क्षेत्रों से या अन्य परियोजनाओं से पलायन होकर आते है। पर्यावर्णीय क्षति की लागत को भी सामाजिक लागत–अनुलाभ में जोड सकते है। विदेशी विनियम घटक का आंकलन हम नियन्त्रित विनिमय दर द्वारा नही कर पायेगें। इस प्रकार की लागत का आंकलन एक उच्च दर से किया जाऐ तो वह विदेशी विनिमय बाजार का वास्तविक स्वरूप दर्शाएगा। कई अर्थशास्त्रियों का अक्सर सुझाव होता है कि विदेशी विनिमय लागतो को 1.5 से गुणा कर देना चाहिए।

जैसा उपर देखा गया है कि समाज से ताल्लुक रखने वाली लागते अत्यन्त ही जटिल होती है और इसीलिए सामाजिक लागत–अनुलाभ विश्लेषण करते समय हमें अत्यन्त ही सावधानी से काम करना होगा।

लागत के माप की तरह ही अनुलाभ का माप करते समय भी हमे भारी कठिनाईओं से जुझना पडेगा तभी हम सामाजिक लागत अनुलाभ विश्लेषण कर पायेगें। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो प्रकार के अनुलाभ होते है इनमें से ज्यादातर तो मुद्रा में नही आकें जा सकते है क्योंकि वे विपणीय सार्वजनिक वस्तुऐं नही है और वे तो अविपणीय असार्वजनिक होती है तथा अनमोल होती है।

उदाहरण के तौर पर हम कह सकते है कि पी.डब्ल्यू.डी. के उच्च मार्ग परियोजनाओं के मोटे अनुलाभ इस प्रकार है।

- जनता व माल का भारी आवागमन जिससे भारी आर्थिक विकास को दिशा मिलती है।
- गतिशील किफायती, सुविधाजनक और विश्वस्त परिवहन सुविधा कम खर्चीली एवं माल की कम क्षति का अनुलाभ।

एक बडा अनुलाभ (उपरोक्त सार्वजनिक कार्य उच्च मार्ग परियोजना) जो कि प्रत्यक्ष है। उसकी गणना आय की बढोतरी के तौर पर की जा सकती है–

- कई वस्तुओं की गति में बढोतरी से।
- यात्री भाडे की बढोतरी से नई सडको के कारण।

इसकी गणना निम्न समीकरण के अनुसार की जा सकती है।

$Y = XxLxE$

यहां पर Y= आय

X= वाहनो की प्रतिवर्ष दोनो तरफ की औसत संख्या

L= नई सडकों की लम्बाई

E= प्रत्येक कि.मी. पर वाहनो की औसत कमाई

यात्रियों व माल की आय का अनुमान अलग से लगाया जा सकता है लेकिन X और E का मूल्य तो प्रत्येक के साथ भिन्न ही होगा। अप्रत्यक्ष अनुलाभ जैसे की सुविधा, आराम, विश्वसनीयता आदि जिन्हें हम मुद्रा में नही आंक सकते है।

सामाजिक लागत अनुलाभ विश्लेषण, एक प्रकार का आर्थिक विश्लेषण एक प्रकार का क्रियाविधि है, जिसका विकास निवेश परियोजनाओं को आंकने के लिए पूर्ण रूप से समाज की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्राथमिक तौर पर जन निवेश के आंकने का इस्तेमाल होता है चाहे निजी निवेश हो चाहे सार्वजनिक निवेश हो। सामाजिक लागत अनुलाभ विश्लेषण द्वारा इन दिनों में काफी मान्यता पाई है। जन निवेश कई देशों में विशेष कर विकासशील देशों में धीरे–धीरे बढ रहा है। जहां सरकारे अपने राष्ट्रों के आर्थिक विकास की और विशेष ध्यान दे रही है।

योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक लागत अनुलाभ विश्लेषण निजी परियोजनाओं के मापन मे सहायक सिद्ध होगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते है कि सामाजिक लागत अनुलाभ विश्लेषण योजना पूर्ण निर्णय लेने से संबंध रखता है।

सामाजिक लागत–अनुलाभ विश्लेषण करते समय निम्न लिखित दिक्कते व परेशानीयां सामने आती है वे निम्न प्रकार है :–

- कुछ अनुलाभ तथा लागतों को हम मुद्रा के रूप में आंक नही सकते है।
- जब अत्यधिक परियोजनाओं की स्थिति होती है, जिसमें कई सरकारी व सार्वजनिक प्रणालीयों की दशा में सत्य होता है, संभावित अनुलाभ को विभिन्न परियोजनाओं में बांटना बहुत की कठिन होता है।

यह ऐसा इसलिए होता है कि संभावित अनुलाभ का वास्तविक हिस्सा जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक परियोजना में नही बांट सकते है। संभावित अनुलाभ तो एक सुदृढ विकसित परियोजना के परिणाम स्वरूप ही माना जाएगा। उदाहरणतः हम सब जानते कि ग्रामीण विकास के परिणामतः कई परियोजनाओं जैसे कि बडी सिचाई व छोटी सिचाई हर प्रकार की सुविधाएं वित्तीय सुविधा खाद व बीज की सुविधा ग्रामीण उधोगो के विकास अन्य कई विकास की परियोजनाओं जिनसे अनुमानित अनुलाभ अच्छा प्राप्त हो सकता हो। ऐसे हालातों में विकासीय अनुलाभों की स्थिति में किसी भी एक परियोजना में बडी ही कठिनाई का सामना करना पडता है।

- सार्वजनिक प्रणाली की परियोजना में जो विकास पर आधारित परियोजनाएं होती है। लोगों की आय वितरण प्रणाली में संशोधन कर सकते है जो कि इन परियोजनाओं का प्रयोग करते है। आय में पुनः वितरण से मूल्य संरचना में बदलाव लाया जा सकता है।
- एक विशेष छुट ब्याज के दर की मान ली जाती है गणना करते समय यह ब्याज की दर जो लागत तथा अनुलाभ की तुलना करते समय सामने आती है। वह वास्तव में टाईम प्रिफरेन्स रेट आफ इन्टरैस्ट के बारें में एक अनुमान मात्र है। इसका मतलब यह होगा कि भविष्य के अनुलाभों पर लगायी गयी ब्याज की दर का फल उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले उपभोग में, कमी लाना होगा। इसके समस्त लागत–अनुलाभ की तुलना तथा उसकी फिजीबिलीटी का विश्लेषण करना होगा।

fu"d"k

लागत–अनुलाभ के सिद्धातों को जनता के उपयोगी परियोजनाओं पर लागु करना बहुत ही कठिन होता है। इस प्रकार के विश्लेषणों के उद्धेश्य हमेशा महत्वपूर्ण होते है। परन्तु ऐसे विश्लेषणों के अभाव में हम विभिन्न प्रकार की जन परियोजना के बारे में सही निर्णय नही ले पाते है। कई प्रकार की जन परियोजनाऐं जैसे सडक बनाना जहां जिसके लिऐ जरा सी भी वित्तीय मदद प्राप्त होना नजर नही आता है। इस प्रकार के कार्यो में बिना किसी विकल्प के लागत–अनुलाभ विश्लेषण की किया जा सकता है क्यों कि इसमें वित्तीय विश्लेषण का तो सवाल ही नही होता है।

lUnHkZ xzUFk lwph

- जालोर का राजनितिक एवं सांस्कृतिक इतिहास–मातृछाया प्रकाशन जालोर लेखक मोहनलाल गुप्ता।
- जिला सांख्यिकीय रूपरेखा जिला जालोर।
- जिला उधोग केन्द्र जालोर –The new Indian Express Industry seks free import of Granite Marble.
- जैन प्रतिमा– राजस्थान में ग्रेनाइट उधोग (समस्याऐं एवं सभावनाऐं) मोहनलाल सुखाडिया विश्वविधालय उदयपुर।
- माहेश्वरी सत्यानारायण – ग्रेनाइट उधोग के विपणन क्षेत्र मोहनलाल सुखाडिया विश्वविधालय उदयपुर।
- राजस्थान सरकार खान एवं भू–विज्ञान विभाग– www.dmgraj.gov.in
- नफा नुकसान पेपर 10 मार्च 2014– Rajasthan Stone and Marble- Jay singh Kothari.
- Ricco.co.in

❖◆❖